Procedure for dealing with appeals

4073. SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the Supreme Court judgement given in R. P. Bhatt Vs. Union of India (AIR 1986 SC 1040);

(b) if so, whether Government have issued any instruction/advice etc. to the ministries/departments/instrumentalities to adhere to the observations/interpretation of the procedure of dealing with the Appeals/Reviews etc. prepared by petitioner-employees under relevant CCS (CCA) Rules; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. The Rule position in the matter is quite clear. The existing instructions already envisage that self-contained, speaking and reasoned order should be passed by the authorities exercising disciplinary powers.

Retrospective effect to DPCs

4074. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Personnel had agreed in 1989 to give DPCs retrospective effect in case it is delayed due to court cases; and

(b) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) No, Sir. Normally, all promotions including those delayed due to court cases take effect only from a prospective date as per instructions issued by the Department of Personnel and Training.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती तथा पदोन्नति की नीति

4075. श्री चुन्नी लाल चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आरक्षित कोटे के तहत भर्ती तथा पदोन्नति की नीति पर विशेष ध्यान दिया जाता है; और

(ख) क्या इन वर्गों का वर्ग ''क'' और वर्ग ''ख'' में कोटा पूरा है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन):

(क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व पिछले कई वर्षों से निरंतर बढ़ता आ रहा है। तथापि, समूह ''क'' और समूह ''ख'' में उनका प्रतिनिधित्व, संबंधित श्रेणियों के संबंध में निर्धारित प्रतिशतता तक नहीं पहुंता है। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को आरक्षण का पूरा लाभ लेने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से उन्हें विभिन्न प्रकार की ढील/रियायतें दी जाती रही है। अत: सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के मामलों में आयु-सीमा में ढील दिए जाने, परीक्षाओं में बैठने के अपेक्षाकृत अधिक अवसर दिए जाने, शुल्क में रियायत दिए जाने, उपयुक्तता के मानकों में ढील तथा अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने आदि का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के संबंध में निर्धारित आयु-सीमा में ढील/रियायत दिए जाने, पदोन्नति हेतु विस्तरित विचारण-क्षेत्र रखे जाने आदि के बारे में भी अनुदेश विद्यमान हैं।

Relaxation in qualifying marks in Written Test and Viva-Voce

4076. SHRI BANGARU LAXMAN:
SHRI GANDHI AZAD:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether *vide* Office Memorandum number 36012/23/96 Estt. (Res), dated the 22nd July, 1997 the relaxation in qualifying marks in written test and viva-voce has been withdrawn with immediate effect;

(b) whether all the posts of Group A, B, C